Drugs & Chemicals Ltd. in Orissa are under various stages of study by BIFR.

देश में सरकारी क्षेत्र के संस्थान

3171. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 के अंत में सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की संख्या 245 थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थानों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ में गत वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान द्वारा शुद्ध लाभ की कितनी राशि अर्जित की गई;

(ङ) इन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और विदेशी ऋणों के रूप में प्राप्त पूंजी का प्रतिशत क्या था; और

(च) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन विदेशी ऋणों पर सरकार को कितना ब्याज देना पड़ा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार केवल जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, परिचालन में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उद्यम थे।

(ग) जी, हां। वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक इन उद्यमों द्वारा अर्जित कि गए लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में उद्यमवार निवल लाभ का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड 1 के पृष्ठ विवरण 42 से 46 में दिया गया है जिसे 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

(ङ) से (च) सामान्य शेयर और ऋणों के रूप में निवेश, विदेशी ऋणों की राशि जिसमें ऐसे ऋणों पर ब्याज की राशि भी शामिल है का उद्यमवार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड III में तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते के सारांश में उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की दशा

3172. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग गत कई वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक उद्योग को कितना घाटा हुआ;

(घ) इन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में पूंजी निवेश की वर्ष-वार राशि क्या थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 से जून, 1994 तक अनेक कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो उन कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) 1992-93 के दौरान केवल जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 104 उद्यमों ने घाटा उठाया है। ऐसे उद्यमों के नाम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके लाभ/हानि और सामान्य शेयर तथा ऋणों के रूप में निवेश का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-I के विवरण संख्या 7 ख और 16 में दिया गया है। जिसे दिनांक 23-2-1994 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ङ) से (छ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्य-निष्पादता में सुधार करने के लिए उद्यम विशेष के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित उद्यम द्वारा कार्रवाई की जाती है। किए गए कुछ उपाय हैं:- आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन योजना बनाना, वित्तीय, प्रबन्धकीय और संगठनात्मक पुनर्गठन करना, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि। खर्च की गई राशि किए गए उपाय की किस्म पर निर्भर करती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजित कार्यक्रम

3173. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने के

लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक रोजगार सृजित कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाना है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्च, 1994 तक रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करके युवाओं को रोजगार दिलाए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने युवाओं को रोजगार दिए गए हैं;

(ङ) इस रोजगार सृजित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुल कितनी राशि व्यय किये जाने का लक्ष्य है; और

(च) इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा कौन से स्रोत निर्धारित किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक स्रोत से कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) 3 वर्षों के दौरान 1.12 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) जी, हां।;

(घ) विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन मार्च, 1994 तक उपलब्ध कराए गए रोजगार के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

1.	सहरसा, बिहार	10,200
2.	कालाहांडी, उड़ीसा	377
		10,577

अन्य 19 जिलों से संबंधित कार्य अभी आरंभ हुआ है।

(ङ) और (च) 3 वर्ष के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 11,634 लाख रुपये की कुल निधि अपेक्षित होने का अनुमान है। डी आर डी ए और बैंक से निधि सहायता प्राप्त होने की आशा है। कुल अपेक्षित निधि में डी आर डी ए, बैंक और के.वी.आई.सी. की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत की दर से होने का अनुमान है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिश पर रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

3174. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए की गई सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद भी रुग्ण इकाईयां रुग्ण ही बनी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है, और;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Sick industrial units

3175. **SHRI VIRENDRA KATARIA:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the names of the big industrial units in different States including Punjab, Haryana and Himachal Pradesh which have fallen sick; and

(b) what steps Government have taken for the revival of these sick units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Reserve Bank of India compiles data regarding sick industrial units assisted by the banks in the country. According to Reserve Bank of India, the number of sick industrial units in the Non-Small Scale Sector as on 31st March, 1992 in different states including Punjab, Haryana and Himachal Pradesh is as follows:

		No. of Sick Non-SSI Units
1.	Punjab	32
2.	Haryana	55
3.	Himachal Pradesh	22
4.	Toal (Country)	1536

In accordance with practices and usages customary among banks and in confirmity with provisions of statutes governing public sector banks, information relating to individual constituents of the banks is not to be divulged.